

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: 8/विधायी कार्य-16/2023 /यो0वि0,पटना,दिनांक नवम्बर, 2023
प्रेषक,

रविश किशोर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

श्री संजीव मित्तल मा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय: **श्री जनक राम, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद के 205वाँ सत्र में पूछा जानेवाला ऑनलाईन तारांकित प्रश्न सं0-नेवा-1/205/185 के हस्तांतरण के संबंध में।**

प्रसंग : वित्त विभाग का पत्रांक 9898 दिनांक 06.11.2023

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में संलग्न तारांकित प्रश्न संख्या-1/205/185, दिनांक 02.11.2023 में संनिहित "बिन्दु-क" का वांछित उत्तर प्रतिवेदन योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के स्तर से पत्र के साथ संलग्न है। शेष कंडिका का उत्तर वित्त विभाग से अपेक्षित है।

अतएव विषयांकित प्रश्न के कंडिका-1 का उत्तर प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर हस्तांतरित किया जाता है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 8/विधायी कार्य-16/2023 /यो0वि0,पटना,दिनांक नवम्बर, 2023
प्रतिलिपि: सचिव, बिहार विधान परिषद, सचिवालय/विशेष सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 8/विधायी कार्य-16/2023 /यो0वि0,पटना,दिनांक नवम्बर, 2023
प्रतिलिपि: अनु0-सहित विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक: 8/विधायी कार्य-16/2023 5050 /यो0वि0,पटना,दिनांक 07 नवम्बर, 2023
प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री जनक राम, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद के 205वीं सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0-नेवा -1/205/185 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर सामग्री
(क) क्या यह सही है कि योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के SCSP TSP के दिशानिर्देश के अनुसार SC/ST की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान किया जाता है,	स्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल आबादी का 15.9 % एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.28 % है। जिसके आलोक में राज्य योजना के कुल उद्व्यय का 16 % राशि अनुसूचित जाति एवं 1.28 % अनुसूचित जनजाति के कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर्णांकित किए जाते हैं।
(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2018-19 में CAG Report के अनुसार बिहार सरकार ने SCSP बजट के 8800 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग बड़े हाइवे, बांध, मेडिकल कॉलेज एवं बिजली कम्पनियों को लोन अनुदान देने पर खर्च किया है,	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्नाटक, तैलांगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब के तर्ज पर SCSP TSP के संचालन के लिए कानून बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस विभाग से संबंधित नहीं है।

संलग्न :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के योजना उद्व्यय की छायाप्रति संलग्न


(अजय कुमार)
उपनिदेशक

3) *Handwritten text*